नागपुर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रोडमैप तैयार, पर योजना में प्रदुषण के स्त्रोतों पर जानकारी नहीं

नागपुर, प्रेस विज्ञप्ति. 30 जून 2020

नागपुर के साफ़ वायु योजना में प्रदूषण के स्रोतों पर जानकारी की कमी है. इसके विपरीत, चंद्रपुर की योजना महाराष्ट्र की उन पांच शहरी साफ़ हवा योजनाओं में शामिल है जिनमें उत्सर्जन स्रोतों की जानकारी है. प्रदूषण कम करने के लिए किन प्रयासों को प्राथमिकता देनी चाहिए इसका निर्णय लेने के लिया प्रदूषण स्त्रतों पर जानकारी महत्वपुर्ण है. यह बात काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (CEEW) और अर्बन एमिशन की ओर से जारी की गए एक नए अध्ययन में सामने आई है.

भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) ने महाराष्ट्र में 17 सहित देशभर के 102 शहरों को शामिल किया गया है. इसके तहत उन्हें दिशा-निर्देश दिया गया है कि वह जरूरी कार्यक्रमों, उपायों को लागू कर साल 2024 तक 20% से 30% तक पार्टीकुलेट प्रदूषण को कम करें.

सीईईडबल्यू की रिपोर्ट के मुताबिक, नागपुर की योजना में अंकित 80 प्रतिशत कार्यों में देखरेख, प्रस्ताव तैयार करना,

पहचान करना, लांच करना, जांच करना, प्रतिबंध लगाना, जैसी चीजों का उल्लेख किया गया है. इसका तात्पर्य यह है कि केवल 20% प्रयास ही ऑन-ग्राउंड प्रदूषण नियंत्रण के उपाय है.

अध्ययन के मुताबिक नागपुर एक्शन प्लान के तहत 38 प्रतिशत नीतियाँ ट्रांसपोर्ट सेक्टर और 20 प्रतिशत उद्योगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. पूरी तरह से नहीं पर योजना में अंकित गिनी चुनी प्रयासों के लिए ही वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया है.

सीईईडबल्यू की शोधकर्ताओं तनुश्री गांगुली का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान नागपुर में पार्टिकुलेट मैटर (पी एम) 2.5 में 30 प्रतिशत तक की कमी देखी गई है. हालांकि इतने बड़े शहर में मात्र एक रियल-टाइम प्रदुषण माँनिटर लगा है, जिससे पी एम 2.5 के स्तर का पता चल पाता है, यह पर्याप्त नहीं हैं. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नागपुर नगर पालिका को एक से अधिक मशीन लगाकर प्रदुषण पर निगरानी बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए.

सीईईडबल्यू-अर्बन एमिशन के विश्लेषण में यह भी पाया गया है कि नागपुर की योजना में अंकित 66 कार्यों को पूर्ण करने के लिए 17 विभागों को ज़िम्मेदारी दी गयी हैं. जबकि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नागपुर में सभी कार्यों में केवल

20% के लिए जिम्मेदार है. वहीं शहरी स्थानीय निकाय और राज्य परिवहन विभाग लगभग 60% कार्यों का बोझ उठाता है. इसके अलावा 34% काम कई एजेंसियों के अंतर्गत आती हैं. इन सब एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल बनाने की जरूरत है.

नागपुर में अनुमानं 21% प्रदुषण शेहेरी सीमा के बहार स्थित स्रोतों से आता है. इसके बावजूद नागपुर की योजना में रिजनल लेवल पर कॉर्डिनेशन का उल्लेख नहीं किया गया है

सीईईडबल्यू की शोधकर्ता कुरिंजी सेल्वाराज के मुताबिक कई एजेंसियों के बीच में काम का बंटवारा कर दिया गया है, लेकिन उनके बीच में आसपी सामंजस्य नहीं है. सबके बीच में जवाबदेही तय करना जरूरी है. तभी प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया को सही से लागू किया जा सकता है.

चंद्रपुर योजना

चंद्रपुर की योजना में अंकित कार्यों की पूर्ती के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का उल्लेख नहीं किया गया है. चंद्रपुर में उद्योंगों के अधिक होने से यहां प्रदूषण अधिक है. चंद्रपुर शेहेर की साफ़ वायु योजना में 30 प्रतिशत कार्य बिजली उत्पादन और अन्य औद्योगिक प्रदूषण को कम करने पर केंद्रित किया है.. औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए अंकित कार्यों की पूर्ती के लिए केवल एक साल का समय निर्धारित किया गया है.

सेल्वाराज के मुताबिक चंद्रपुर जैसी योजनाओं के लिए, जिसमे अधिकतर कार्य अल्पकालिक है, योजना में लिखित कार्यों की पूर्ती के लिए वित्तीय आवश्यकताएं का अंकन और भी महत्वपूर्ण हो जाता हैं। साथ ही, सभी जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा प्रयासों को ट्रैक करने के लिए एक को मोनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए

इस अध्ययन के मुताबिक महाराष्ट्र में स्थित 17 नॉन-अटैंमेंट शेहेरों की योजनाओं में से केवल पांच शेहेरों - कोल्हापुर, अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपुर और मुंबई की योजनाओं में प्रदुषण के स्त्रोतों पर जानकारी है. लेकिन इस जानकारी का इस्तेमाल प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों को प्राथमिकता देने में नहीं की गयी है.

इसके अलावा केवल 6 शहरों - अमरावती, बदलापुर, नासिक, मुंबई, सोलापुर और पुणे, की योजनाओं में ही वित्तीय आवश्यकताओं का उल्लेख है.

अच्छी बात ये है कि 17 शेहरों के क्लीन एयर प्लान एक दूसरे से अलग है. लेकिन, प्रदूषण स्त्रोतों से होने वाले उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य, शहर-विशिष्ट प्राथमिकताओं और किये जाने वाले कार्यों के लिए रिपोर्टिंग मैकेनिज्म का ना होना राज्य में योजनाओं के कार्यान्वयन को पटरी से उतार सकता है।

स्टडी प्रोसेस

सीईईडबल्यू-अर्बन एमिशन ने स्वच्छ वायु कार्यक्रम की व्यापक समीक्षा की है. इसके लिए इस योजना से जुड़ी एक-एक पहलू का अध्ययन किया गया है. अध्ययन के तहत प्रदूषण से जुड़े कानून, पॉल्यूशन के स्त्रोत की जानकारी, इसपर काम कर रही संस्थाओं की जिम्मेदारी आदि का गहन आकलन किया है. गहन आकलन इसलिए भी है क्योंकि इन सब मुद्दों पर जानकारी जुटाने के लिए कुल देशभर में चल रहे स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शामिल 102 शहरों की योजनाओं का अध्ययन किया गया है. इसके तहत देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे योजनाओं का आकलन किया गया है.

सीईईडबल्यू के बारे में

काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईई**बल्यू**) एशिया के अग्रणी नॉट फॉर प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च संस्थानों में से एक है. काउंसिल संसाधनों के इस्तेमाल, उसका दुबारा इस्तेमाल कैसे हो जैसी चीजों पर भी काम करती है. इसके लिए डेटा, डेटा का विश्लेषण, उसके इस्तेमाल की योजना बनाने के एक्सपर्ट के तौर पर काम करती है. साथ ही निजी और सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर रिसर्च करती है. इसके रिसर्च की क्वालिटी को विश्व स्तर का माना जाता है. साल 2020 में 'ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट-2019' में नौ

कैटेगरी में अपना स्थान बनाया है. परिषद को दुनिया के शीर्ष जलवायु परिवर्तन थिंक टैंकों में भी लगातार स्थान दिया गया है. लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें @CEEWIndia पर फॉलो करें.

अर्बन एमिशन के बारे में

अर्बन एमिशन एक स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान है जिसकी स्थापना वायु प्रदूषण से संबंधित सूचना, अनुसंधान और विश्लेषण के लिए की गई थी. यह देशभर में एयर क्वालिटी की भविष्यवाणी, उसका प्रचार-प्रसार, उससे संबंधिक स्टडी करती है, खासतौर पर दिल्ली में. यह संस्था वायु प्रदूषण संबंधी रिसर्च, सूचना आदि का प्रदर्शन भारत, अफ्रीका, एशिया के कई देशों में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए प्रदर्शित करती है. भारत में 50 और एशिया-अफ्रिका के देशों में 10 से अधिक प्रदर्शन कर चुकी है. अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए ट्विटर पर फॉलो करें- @urbanemissions

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें-

रिद्धिमा सेठी - riddhima.sethi@ceew.in : 9902039054

मिहिर साह - mihir.shah@ceew.in